

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिपा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 7 अप्रैल 2026 मंगलवार

सम्पादकीय

मंहगा होता सफर

देशभर में मंहगाई में बढ़ोतरी के बीच अब लोगों के लिए कहीं आना-जाना भी मंहगा साबित होने लगा है। दरअसल, वैश्विक परिस्थितियों की वजह से पहले ही संकट का दायरा फैल रहा है और चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस बीच हरियाणा में राजमार्गों पर टोल दरों में बेतहाशा वृद्धि की घोषणा आम लोगों के सामने एक नई परेशानी पैदा करने वाली है। इसके अमल में आने के साथ ही निजी वाहनों से यात्रा करने वालों को अब अधिक टोल चुकाना होगा। यह हाल तब है, जबकि अधिकतर राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, आए दिन लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एकल और दोहरी यात्रा में पांच सप्ताह से लेकर पैंतीस रूपय तक की बढ़ोतरी पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। मसलन, गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस-वे पर बजघेड़ा टोल प्लाजा पर एकल यात्रा के लिए 225 रूपय देना यात्रियों के लिए भारी साबित हो सकता है। दूसरी ओर वाणिज्यिक वाहनों से वसूली का अंतर भी दिखेगा और आखिरकार आम आदमी पर ही इसकी मार पड़ेगी। सवाल है कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार किए बिना टोल दरों में वृद्धि की क्या तुक है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजमार्गों पर यात्रा मंहगी किए जाने से लोगों में निराशा बढ़ेगी।

इस समय ज्यादातर राजमार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। वहीं रास्ते में साफ-सुथरे जन-सुविधा परिसरों का अभाव खटकता है। रात में कई मार्ग पर अंधेरा होने से हादसों का अंदेशा बना रहता है। राजमार्गों प्राधिकरण के गरीबी दल तुरंत नौके पर नहीं पहुंचते। इससे लोग असहाय स्थिति में होते हैं। कई बाव हादसों के बाद फिर हादसा होगा यह बताता है कि प्राधिकरण को टोल की तो पिला है, लेकिन यात्रियों की जान की नहीं। अक्सर देखा गया है कि टोल नाकों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इससे न केवल समय की, बल्कि ईंधन की भी बर्बादी होती है। हालांकि हरियाणा में टोल पर अब केवल फास्टेग या आनलाइन मुतातन ही किया जा सकेगा। ऐसे में संभव है कि वाहनों की कतार कुछ कम हो। फिर भी राजमार्गों पर सुविधाएं बढ़ाए बिना टोल शुल्क बढ़ाना यात्रियों पर नाहक ही बोझ डालने जैसा है।

ट्रम्प की मनमानी

अमेरिका ने एक साहसिक कार्रवाई में ईरान में मार गिराए गए अपने विमान के पायलट को बचाकर अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, पर इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ईरान जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के रवैये को देखते हुए एबी लगता है कि यह युद्ध जारी रहेगा। यदि ऐसा होता है तो पहले से ही दुनिया के लिए समस्या बना उर्जा संकट और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। इस उर्जा संकट का कारण समुद्री मार्ग होमोज़ुग का बाधित होना और साथ ही ईरान की ओर से खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों समेत वहां के उर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना भी है। बाधित होमोज़ुग विषय के साथ-साथ अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप होमोज़ुग मार्ग खुलवाने के लिए अपने दावे को अनुरात ईरान पर भीमका हमले करते हैं तो भी यह कहना कठिन है कि वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे।

ऐसे आसार इसलिए नहीं दिखते, क्योंकि ईरान अनुमान से अधिक घातक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। उसने अपनी नौका क्षमता से अमेरिका को चौंकाया ही है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोलने के पहले उसकी सैन्य क्षमता का सही तरह आकलन नहीं किया। यह अमेरिका इजरायल का साथ नहीं देता तो इस युद्ध की नीबट ही नहीं आती। स्पष्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को वेनेजुएला समझा और अपने अहंकार के चलते बिना कुछ ज्यादा सोचे-विचारे उस पर हमला बोल दिया।

ट्रंप कुछ भी दावा करे, ईरान में न तो सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है और न ही यह कहा जा सकता है कि परमाणु हथियार निर्माण की उसकी क्षमता पूरी तौर पर नष्ट हो गई है। ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, जिन्होंने मसलने तर्कों से किसी अन्य राष्ट्रपति से सैन्य हस्तक्षेप किया हो। लेकिन इराना अवश्य है कि वे कुछ ज्यादा ही मनमानी का परिचय दे रहे हैं। इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति का आवश्यकता से अधिक अधिकारसंपन्न और एक तरह से निरंकुश होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति की निरंकुशता लोकतंत्र में एक अस्वतंत्रकारी व्यवस्था ही है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के विपरीत है। ट्रंप का रवैया शायद ही बदले, लेकिन अमेरिका के लिए इस पर विचार करना आवश्यक है कि अपार शक्तियों से लैस अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे पूरी दुनिया के समक्ष संकट खड़ा कर देता है। यह ठीक है कि लोकतंत्र होने के नाते आगामी मध्यवर्धि चुनाव में ट्रंप को राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता तेजी से गिर रही है, लेकिन फिलहाल तो उनके मनमाने एजेंडे पर कोई रोक लगती नहीं दिख रही है।

युद्ध का दुष्प्रभाव और पलायन की विवशता



—ज्योति मल्होत्रा—

यदि ईरान व अमेरिका-इराक़ल युद्ध चला चला तो आयातित तेल व उर्वरक और मंहगे होंगे। वहीं जीडीपी अनुमानों में बदलाव के संकेत भी आर्थिक पर असर डाल सकते हैं। प्रवासियों को मुश्किलों से उबरने में मदद चाहिये। फिलहाल रसोई गैस की समस्या से प्रवासी अपने गांव लौट रहे हैं। पहले उन्हें वहीं रहने को आश्चर्य कर, जिसे वे घर कहते हैं।

ऐसे में जब भारत पश्चिम एशिया में युद्ध से पैदा हुए तेल-गैस संकट से निवर्तन में लगा है, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गयी है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक, जहाँ भी प्रवासियों की बड़ी आबादी है, 5 किलो वाले छोटे रसोई गैस सिलिंडरों की उपलब्धता में कमी के कारण वे उत्तर प्रदेश और बिहार के अपने गांवों को लौटने को मजबूर हो रहे हैं। हालात हर्गिज जसे नहीं जैसे सन् 2020 में थे, जब देश में कोविड महामारी फैली थी और रातोंरात लोकडायन घोषित कर दिया गया था। तब सप्ताह, 'द हिन्दू' ने एक पत्राचार— दीपकमल कोर, नीरज बगवा और शिवानी भाऊ— ने पाया कि वैसे तो हर जगह वैसाखी के आसपास प्रवासी हमेशा से जाते रहे हैं, जब रबी फसल की कटाई हो चुकी होती है, मजदूरी मिल चुकी होती है और मालिक अपने वाले नए साल की खुशी से सरवाहो होते हैं— एक बार फिर से क्षितिज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वित्तातुर प्रवासी जो आशंका जता



रहे हैं, वह हो भी सकता है, कह रहे हैं कि यदि हो गया तब होगा। निश्चित तौर पर यह युद्ध भारत व दुनिया को अपनी बेहतरीन योजनाओं पर फिर विचार करने को मजबूर कर रहा है।

देश के भीतर, मोदी सरकार रुपये की गिरती कीमत को थायरक रखने को प्रयासरत है— एक महीने 26 फरवरी को अली खामेई की हत्या के साथ संकट शुरू होने से पहले, भाव 90 रुपये प्रति डॉलर पर था, और पिछले हफ्ते इसने 95 रुपये प्रति डॉलर तक बढ़कर सीमा भी पार ली थी, जिसके बाद आर्थिक वापसी भी की। तेल का दाम बढ़ने को फिलहाल थाम रखा था। तब सप्ताह, 'द हिन्दू' ने एक पत्राचार— दीपकमल कोर, नीरज बगवा और शिवानी भाऊ— ने पाया कि वैसे तो हर जगह वैसाखी के आसपास प्रवासी हमेशा से जाते रहे हैं, जब रबी फसल की कटाई हो चुकी होती है, मजदूरी मिल चुकी होती है और मालिक अपने वाले नए साल की खुशी से सरवाहो होते हैं— एक बार फिर से क्षितिज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वित्तातुर प्रवासी जो आशंका जता

का 20 प्रतिशत भी इसी रास्ते से आता है।

ईरान यूरिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। एक आम नाइट्रोजन उर्वरक है। ईरानी हमलों के बाद कतर ने अपने गैस संयंत्र बंद कर दिए— वह दुनिया के 14 फीसदी यूरिया का आपूर्तिकर्ता है। भारत दुनिया में उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब आर्थिक पूरी तस्वीर साफ हो गई होगी। अगर ईरान युद्ध जारी रहता है व खाद बनाने वाले घटकों की सप्लाई में रुकावट आती है— दुनिया के अन्य उत्पादन का करीब आधा हिस्सा स्थितिहीक नाइट्रोजन खाद पर निर्भर है— तो गरीबों और ज्व्यादा मुश्किल में पड़ जायेंगे।

इस बीच, जैसे-जैसे यूरोप ट्रंप से तारा आ रहा है— फ्रांस, स्पेन और जर्मनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की दोहरी बातों पर संशय नाराजगी व्यक्त की है। एक एक तरफ व युद्ध रोकने की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर शैवानी के अमेरिकी सेना इराक़ुरी फारसी स्थानता को पुनर्गठित करने के लिए ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे, जैसे पत्त, बिजली लाइन्स आदि को निशाना बनाएगी— शक्ति संतुलन

के बदलने के आरंभिक संकेत शायद अब मिलने लगे हैं।

कुछ दिनों से होमोज़ुग जलमरु क्ख पर जहाजों से टोल टैक्स युआन में वसूलना शुरू हो चुका है। तब शुक्रवार, भारत के लिए तैल ले जा रहा एक जहाज रास्ता बदलकर अब चीन की तरफ बढ़ रहा है। सामान्य कामकाज में बन जाने वाली अहलता अजीब बात नहीं— आखिर युद्ध जारी है और भारत भी उससे अछूता नहीं— इस माल खंडी रास्ते में होने वाले चुनौतियों को लेकर गम्हाणगी छापी है। मसलन, भारत के रास्ते का सियासी नक्शा इस चुनाव या अगले साल होने वाले कुछ विधायक चुनावों के बाद बदल भी सकता है और नहीं भी— लेकिन सत्ताधारी भाजपा को निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं। प्रधानमंत्री हम्शा बाद अपने जोश के साथ देश के एक कोने से दूसरे में जा रहे हैं। जब अरबम में वे चाय वागाम में महिला मजदूरों के साथ चाय की पियायें तोड़ते नजर आए हैं वहीं इससे कुछ दिन पूर्व, और बाद में, पुडुचेरी, तमिऴनाडु व केरल में रैलियों को संबोधित किया।

शायद युद्ध की वजह से पैदा

हुई बेचोनी पिछले महीने वॉशिंगटन युद्ध डीसी स्थित एक थिंक टैंक, पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट से और भी बढ़ गई। इस थिंक टैंक की अगुवाई अरविंद सुब्रमन्यम कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इस वकिम पेपर में 'भारत के जीडीपी आकलनों में पिछले 20 साल से हो रही गलतियों' के नए सतूत पेश किए गए हैं। अर्थशास्त्री के तर्कों का मुख्य बिंदु है कि 2005 से 2011 के बीच के तेजी के सालों में— भारत ने शायद कभी अपनी आर्थिक विकास दर 1—1.5 फीसदी अंक कम करके आंकी थी, जबकि 2012—2023 के बीच अपनी आर्थिक विकास दर को 1—1.5 प्रतिशत अंक जवाब करके आंका है। रोक यह कि जिस आधे दशक में दर कम करके आंकी गई, वह मनमोहन सिंह के कार्यकाल से मेल खाती है जब पूर्व प्रधानमंत्री ने आर्थिक तारकीकी पान में 'पुनितन रिपरिड' (सखत आशावाद) जगाने का आह्वान किया व एक महत्वाकांक्षी का निर्माण किया। जबकि, जोडी के शासन काल बढ़ दशक में मिसमें आर्थिक वृद्धि को बढ़ाकर आंका गया, इस कालखंड की मुख्य पहचान नोटवर्दी, जीएसटी की शुरुआत और कोविड महामारी है— जहािर है, इनमें महामारी उन्की गलती नहीं है।

सुधामन्यम के अनुसार, जीडीपी का आकलन बढ़ाकर करने का एक कारण यह है कि भारत ने 2011—12 से जीडीपी मापने के लिए डेटा सभित अपने स्रोत और आकलन विधि बदल दी है— साल 2011—12 से 2016—17 तक के सरकारी अनुमानों के अनुसार अलग-अलग तरीके से जीडीपी वृद्धि लगाने में यह 4.5 प्रतिशत रही होगी। वहीं 2005—2011 की अवधि में, जब जीडीपी का अनुमान 7 प्रतिशत था, जिकिर वास्तव में यह 8—8.5 प्रतिशत रही होगी।

सुधामन्यम आगे कहते हैं कि बढाकर दिखाया गया जीडीपी अनुमान कुछ हद तक मानने की विधि में बदलाव से जुड़ा है, जब अर्थव्यवस्था में छेत्ता सा अंश रखने वाले औपचारिक क्षेत्र को विशाल अनौपचारिक क्षेत्र का नमूना प्रतिनिधि (प्रिविडी) मानकर गणना की गई— कुछ लोगों का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा सकल अर्थव्यवस्था के 94 प्रतिशत जिताना तक बढ़ा है। उनका कहना है कि इस नए सतूत का असर मौजूदा अर्थव्यवस्था पर होगा, जीडीपी पर और उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर भी। फिर भी, राजनीतिक स्थिरता की धारणा एक अजीब चीज है। बहुत साल पहले, 1991 में, जब मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर अपना श्थम बजट पेश किया, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह बरसपराई हुई थी, तब उन्होंने विद्वत् बहूगो का हवाला देते हुए कहा था 'धरती पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती, जिस्का सम्य आ गया हो'। 2014 में, उनके नेतृत्व में प्राणु जवदरत आर्थिक वृद्धि के वाजुद, प्रथममंत्री मनमोहन सिंह की पार्टी मोदी की जाणपा से सत्ता हार गई— उस वक्त निधुरता एवं शोक—शरारा वाले इस उन्मीद हावी थी कि मोदी सरकार देश में कुछ स्थिरता लाएगी।

एक बार फिर वही समय है। अगर सुधामन्यम की मानें तो— और अब तक किसी ने भी उनके वकिम पेपर का खंडन नहीं किया— तो विश्वास के मौजूदा सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ी है। इस विश्वास में यदि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण बुनियाद में बनी अस्थिरता भी जोड़ लें— और अगर यह युद्ध जारी रहता है, तो न केवल तेल व उर्वरक की कीमतों पर बरक मास्तर पर संकट अरब पर पड़ सकता है।

निश्चित तौर है समस्याएं भारत द्वारा पैदा नहीं की गयीं। तथ्य यही है कि भारतीयों को इन मुश्किलों से उबरने को मदद की जरूरत है। वतौर शुक्रवार, आएर हम प्रवासियों को उरबी आशंका बने रहने को आश्चर्य रखे, जिसको वे अपना कर सकते हैं।

—वेडेल द हिन्दू की प्रवान संपादक है।

आम आदमी पार्टी अपनों के हाशिये पर क्यों ?

—सौरभ वाण्ये—

आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक नई उन्मीद जगाई थी। ब्रह्मचार के खिलाफ आंदोलन से उभरी पार्टी पारदर्शिता, ईमानदारी और जनगोदीदारी के वादों के साथ आजादी वाले तैवर के साथ नाथक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आए ने दिल्ली में शिवा, स्वास्थ और बिजली—पानी जैसे मुख्य मुद्दों पर उल्लेखनीय काम कर लोगों का विश्वास जीता। लेकिन समय के साथ कई ऐसे कारण सामने आए हैं, जिनसे जनता के एक वर्ग में आप पार्टी मोहभंग की स्थिति बनी है। शुरुआत में 'आप' ने नई राजनीतिक का दावा किया था, लेकिन समय के साथ ही परंपरागत राजनीतिक रणनीतियाँ अपनावने के आरंभ लगे।

दल-बदल, राजनीतिक समझौते और सत्ता बनाए रखने की प्रार्थनाओं ने इसको एक आदर्श पर सवाल खड़े किए। जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार को खिलाफ लड़ाई से शुरुआत की, उसी पर अब विमिन घोटालों की शरार लगे हैं। खासकर दिल्ली की शरार नीति को लेकर उद विवाद ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। इससे जनता के बीच भरोसे में कमी आई है। समय-समय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का साहर होना या निफासन जैसे कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का अलग होना, संगठन के भीतर अहमति और केंद्रीकरण की ओर इशारा करता है। धीरे-धीरे यह नई उन्मीद वाली पार्टी अपनों के हाशिये पर क्यों है यह चिंतन का विषय है।

दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और उसके युवा बहरे राष्ट्रपत्या राघव चड्ढा के बीच उभरने वाले फिगर एक बार पुरानी बेलत में नई शरार वाली स्थिति व इक्को लेकर आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला कल एक व्यक्ति और पार्टी के बीच मनेबत का नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों में अनुशासन, पारदर्शिता और नैतिक शैली की भी परीक्षा है। इसका जीता जागता उदाहरण पहले भी सामने आए हैं जिनमें प्रसिद्ध कवि



कुमार विश्वास सहित अन्य बहरे अरग हो गए। कुमार आप पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जो अरविंद केजरीवाल के साथ उस दौर से थे जब उन्होंने अपनी नौकरी संहित खेव कुछ दाव पर लगाकर साथ दिया था। उनके बाद आम आदमी पार्टी में कई दौर आए हैं जिनमें अन्य कावडर नेतृत्व योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांतिजिटा, आशुतोष कपिल मिश्रा अलका लामा, कैलाश गहलोत, मयंक गांधी, अंजलि दमाविया, गुमाय वारे, आनंद कुमार सहित अन्य नाम भी साथ छोड़े चुके हैं व खासि मालीवाल आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। अब एक बार और शांति हो रहा है यह है राघव चड्ढा, जो कि प्रमुख युवा नेताओं में गिने जाते हैं, कम समय में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच विश्वास की स्थिति को उजागर मनेबत दे उजागर किया है। आओ-प्रत्याश, निर्णय प्रक्रिया में मतेबद और व्यक्तित्व महत्वाकांक्षायें समी तल इस विवाद को जटिल बनाते हैं।

राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति से बड़े होते हैं। आप ने हमेशा सामूहिक नेतृत्व और पारदर्शिता का वाद किया है। ऐसे में यदि पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से अलग रुख मनेबत का नहीं, यह संगठनात्मक अनुशासन पर प्रभावित लगाता है। दूसरी ओर, लोकतंत्र में व्यक्तित्व विचारों की अभिव्यक्ति भी उन्की ही महत्वाकंक्षा है। आप ने खुद को एक

वैकल्पिक और स्वच्छ राजनीति के प्रकलन रूप में स्थापित किया था। इस तरह के विवाद पार्टी की उस छवि को धक्का पहुंचा सकते हैं। विषय के लिए यह एक अवसर बन जाता है कि यह पार्टी की आंतरिक एकता और विश्वासनीयता पर सवाल उठाए। यह विवाद आप नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। एकसे अहमति और संतुलन है। क्या पार्टी संवाद के जरिए समझाना निकालती है या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सरता आदेश देती है, इससे नैतिक राजनीति तय होगी।

आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच का यह टकराव भारतीय राजनीति के उस व्यापक सच को सामने लाता है, जहां व्यक्तित्व महत्वाकांक्षा और संगठनात्मक अनुशासन के बीच संतुलन बनाना मुश्किल नहीं होता। यदि इसे समझदारी और संवाद से सुलझाया गया, तो यह पार्टी को और मजबूत बना सकता है। वरिष्ठ नेताओं के बीच तकराव उभरना विवाद बढ़ता है, तो इसका असर न केवल पार्टी बल्कि उसके विश्वासनीयता पर भी पड़ेगा।

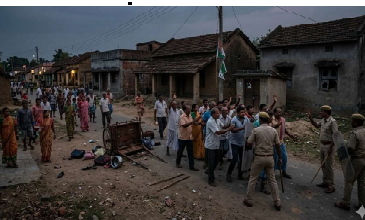
आप पर यह आरोप भी लगाया रहा है कि पार्टी में निर्णय लेने की शक्ति कुछ लोगों तक सीमित हो गई है। इससे सामूहिक नेतृत्व की अभावपूर्ण कमीजरी हुई है। हालांकि दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, लेकिन अन्य राज्यों में विस्तार के दौरान आप को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। चुनाव में सत्ता बिकरण के बावजूद चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिससे पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर असर पड़ेगा है।

पश्चिम बंगाल 6-7 तारी अराजकता

—ललित गर्ग—

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संकटकाल में गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर हो रही प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक अस्थिरता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केल्वर राजनीतिक प्रतियर्था का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति बढ़ते संशय और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मारदाव जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अवधि पर अंतर्भाव को लेकर विषय प्रकर का संश्लेष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटाना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावक लागू होते हैं। यदि इन प्रक्रिया को राजनीतिक चरमे से देखा जायगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एक्सपर्ट प्रक्रिया में बाकब बने हुए जिले तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, जो न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतांत्रिक के तिर्ये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विध्वंसकारी प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीडतंत्र के आगे धुंक्ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएँ भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल लोकतंत्र के शासन पर प्रभावित लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंतुलनशीलता को भी उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक



हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का दौर दोहरा हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के तंत्रे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति अस्थिरता और हिंसा की घटनाएं सामने-समय पर सामने आती रही। सत्ता परिवर्तन के बाद पुनर्गठन कोस्र एवं मरता बर्ननी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आयी है। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक तल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्यापक एक गहरे संकट है। वर्तमान परिस्थिति में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में तनी अधिकारियों को बंधक बनाए गए यह संज्ञाते है कि कुछ तल चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकारों पर सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार के कुछ निर्देशों को अमान्य कर दिया है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की गोपनीय महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रभाव खड़े करती है।

